भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1826
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: तिलहन उत्पादन

1826. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादकता बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में तमिलनाडु के योगदान पर प्रकाश डालते हुए विगत पांच वर्षों के दौरान देश में तिलहन उत्पादन का ब्यौरा क्या है;
(ख) एनएफएसएम- तिलहन, बीज मिनी-किट, प्रदर्शन और एमएसपी संचालन जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सहयोग से तिरुवन्नामलई सहित तमिलनाडु के प्रमुख तिलहन उत्पादक जिलों ने मूंगफली, तिल और सूरजमुखी जैसी फसलों के क्षेत्र, उपज और उत्पादन में किस हद तक योगदान दिया है;
(ग) किसानों की आय, उन्नत किस्मों को अपनाने और राज्य में खाद्य तेल आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के संदर्भ में केंद्र सरकार के उपायों के मापने योग्य परिणाम क्या हैं; और
(घ) अनुसंधान सहायता, प्रौद्योगिकी प्रसार, मशीनीकरण और बाजार संपर्कों के माध्यम से तमिलनाडु में तिलहन उत्पादन को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): देश में तिलहन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 359.46 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 429.89 लाख टन हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर और तमिलनाडु के लिए तिलहन का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज का विवरण इस प्रकार है:

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में, उत्पादन लाख टन में और उपज किग्रा/हे. में)

वर्ष	**अखिल भारतीय**			**तमिलनाडु**			**कुल उत्पादन में तमिलनाडु का % योगदान**
	क्षेत्र	**उत्पादन**	**उपज**	**क्षेत्र**	**उत्पादन**	**उपज**	
2020-21	288.34	359.46	1247	4.74	10.63	2244	2.96
2021-22	289.45	379.63	1312	4.32	10.83	2505	2.85
2022-23	302.39	413.55	1368	4.15	9.49	2288	2.29
2023-24	301.92	396.69	1314	4.01	9.17	2287	2.31
2024-25	304.40	429.89	1412	4.06	8.12	1998	1.89

स्रोत: UPAg पोर्टल

तमिलनाडु में मूंगफली, तिल और सूरजमुखी का उत्पादन होता है। तमिलनाडु राज्य में तिलहन की फसल-वार, जिलेवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज की जानकारी https://upag.gov.in/ पर उपलब्ध है।

घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी गई थी।

एनएमईओ-ओएस का क्रियान्वयन बाजार संपर्क के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर किया जा रहा है। मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का संचालन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों तथा अन्य एजेंसियों जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक किसान को एक हेक्टेयर तक निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले बीज तथा उत्तम कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह मिशन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से तेल निकालने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कटाई के बाद की अवसंरचनाओं (तेल मिलों) की स्थापना एवं उन्नयन का भी समर्थन करता है। अलग-अलग कैटेगरी के प्रदर्शन भी क्लस्टर मोड में किए जाते हैं।

प्रजनक बीज उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत सहायता के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में नए सीड हब और सीड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता देकर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की उपलब्धता को मजबूत किया जाता है। तमिलनाडु में पाँच (5) सीड हब (मूंगफली, तिल और अरंडी) और एक (1) सीड स्टोरेज यूनिट स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने, बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा करने, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार हर साल तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत खरीद में तिलहन भी शामिल हैं और इससे किसानों को बेहतर मूल्य और आय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

******